ISSN-0970-0718

जागृति

वर्ष:60 अंक:7 मुम्बई जून 2016

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा पीएमईजीपी हेतु जम्मू-कश्मीर सरकार की सराहना

जम्मू-कश्मीर में 2015-16 के दौरान 2200 पीएमईजीपी ईकाइयों की सहायता हेतु 38 करोड़ रुपये का उपयोग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

ISSN-0970-0718

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
वर्ष 60 अंक 7 मुम्बई जून 2016

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
अरुण कुमार झा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार - अनुप खोडस्कर

कलाकार - दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित

टेलिफैक्स: 022-26719465

ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

सम्पादक: के. सुब्बाराव राव

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रू. 100/-
वर्ष के लिये सदस्यता शुल्क	:	रू. 250/-

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 34

जम्मू-कश्मीर में 2015-16 के दौरान 2200 पीएमईजीपी ईकाइयों की सहायता.....
कलराज मिश्र द्वारा श्रीनगर में खादी कताई एवं बुनाई केन्द्र का उद्घाटन.....
श्रीनगर में नयी पहल.....
स्थानीय उद्योगों के उन्नयन हेतु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर.....
देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि.....
बदलते आर्थिक परिदृश्य में क्लस्टर विकास से बिजनेस प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी.....
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, मुंबई में डी.बी.टी. पी. पर पी.एम.ई.जी.पी. बैंकर्स समीक्षा बैठक.....
हिसार में माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यक्रमों.....
दिनांक 26 मई, 2016 को आयोग मुख्यालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग.....
केन्द्रीय ऊर्जा एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सेवापुरी, वाराणसी का दौरा.....
खादी और ग्रामोद्योग आधारित उद्योगों को विकासशील बनाना है.....
आयोग के अध्यक्ष द्वारा न्यायिक मामलों से सम्बंधित पुस्तिका का लोकार्पण एवं.....
माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खादी की बिक्री में बढ़ोतरी.....
अध्यक्ष महोदय ने कहा, एक गांव को गोद लें.....
पी.एम.ई.जी.पी. कार्यक्रम, सीधे लाभ हस्तांतरण करने में अधिकतम पारदर्शिता.....
खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रगति के राह पर.....
उज्जैन में कुम्भ मेला के दौरान खादी बाजार सिंहस्थ-2016 आयोजित.....
सोलर पैनल इंस्टालेशन ट्रेनिंग.....
आयोग ने सरकार से "मधुमक्खी" को राष्ट्रीय कीट के रूप में घोषित करने.....
खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि.....
आईटीडीसी के होटल में दिखेगा खादी का उपयोग.....
डी.एल.टी.एफ.सी. द्वारा आयोग की पीएमइजीपी योजना के तहत 26 आवेदनों.....
स्वच्छ भारत - स्वच्छ आयोग .....

लेख.....34 से 38

गांधी और खादी:एक प्रासंगिक अनुचिंतन.....
-डॉ.चन्द्रकुमार जैन
मधुमक्खी पालन उद्योग

खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों की झलकियां.....39 से 41

कलराज मिश्र द्वारा पीएमईजीपी हेतु जम्मू-कश्मीर सरकार की सराहना

जम्मू-कश्मीर में 2015-16 के दौरान 2200 पीएमईजीपी ईकाइयों की सहायता हेतु 38 करोड़ रुपये का उपयोग

वर्ष 2015-16 के दौरान जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए राज्य के कार्य की सराहना करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य में 3,772 पीएमईजीपी ईकाइयों के अर्न्तगत 23,140 लोगों को रोजगार दिया गया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2200 से ज्यादा पीएमईजीपी ईकाइयों में रिकॉर्ड संख्या दर्ज करते हुए दो वर्षों में सहायता के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई। रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि भारत वर्ष में 92,508 पीएमईजीपी ईकाइयों की स्थापना के द्वारा पिछले दो वर्षों में 6,80,000 लोगों को रोजगार दिया गया, जिनमें से 23,140 लोगों को जम्मू-कश्मीर राज्य की 3,772 ईकाइयों में रोजगार दिया गया।

इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने होटल प्रबंधन राजबाघ संस्थान में पीएमईजीपी कार्यशाला का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा भी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि 29 मई, 2015 की राजपत्र अधिसूचना

में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पुनरुद्धार और पुनर्वास का प्रारूप अधिसूचित किया गया है, जो एमएसएमई के संरक्षण और विकास को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक सरल और त्वरित तंत्र है। श्री मिश्र ने कहा कि उनके मंत्रालय ने शिकायत निवारण की एक पारदर्शी प्रणाली विकसित की है और यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर सभी शिकायतों को दर्ज करके उनका निवारण करता है।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से देश के विभिन्न भागों में 15 नये प्रौद्योगिक केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। श्री मिश्र ने कहा कि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमों को एक वेब आधारित अनुप्रयोग मॉड्यूल ''माई एमएसएमई'' की सुविधा दी गई है, जिसे मोबाइल एप्प में परिवर्तित किया जा रहा है।

श्री मिश्र ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय हमेशा से हितधारकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग आधार ज्ञापन पर 6,50,000 से ज्यादा ईकाइयों को पहले से ही पंजीकृत किया जा चुका है और 22,00 करोड़ रुपये की लागत से 15 नये प्रौद्योगिकी केंद्र सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आईजीसी साम्बा में स्थित होगा।

हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इच्छा जताई कि जम्मू और कश्मीर में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम इस्तेमाल हो पाया है। उन्होंने राज्य सरकार से और अधिक प्रस्ताव देने को कहा ताकि अधिक सहायता प्रदान की जा सके।

मंत्री महोदय ने कहा कि एनडीए सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि समाज के सभी तबकों को मुख्य धारा में लाया जाए। इससे पूर्व खादी संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में 155 करोड़ रुपये का एमडीए जारी किया जा चुका है।

केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में प्रथम राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी और मार्केटिंग प्लाजा का भी उद्घाटन किया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने हरमुख खादी ग्रामोद्योग संस्थान का उद्घाटन किया था। मंत्री महोदय ने सोरा में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड श्रीनगर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय शिल्पियों को नये मॉडल के 25 चरखे भी वितरित किए।

■■

कलराज मिश्र द्वारा श्रीनगर में खादी कताई एवं बुनाई केन्द्र का उद्घाटन

श्रीनगर: केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री कलराज मिश्र ने आज श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में हरमुख खादी ग्रामोद्योग संस्थान का उद्घाटन किया, जो एक कताई एवं बुनाई केन्द्र तथा खादी वस्तुओं के लिए मार्केटिंग प्लाजा है।

मंत्री महोदय ने सौरा स्थित 90 फीट रोड पर श्रीनगर के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित इस समारोह के दौरान स्थानीय कारीगरों के बीच 25 नये प्रकार के चरखों का भी वितरण किया।

इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि चरखा प्रतिरोध का एक प्रतीक है और यह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों के अधिकतम संख्या में बेरोजगार युवकों एवं महिलाओं की सहायता कर सकता है।

मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्र सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार है और उन्होंने राज्य सरकार से आगे आने तथा नई दिल्ली से अधिकतम सहायता मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार, खासकर, यहां की अराजक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर की प्रगति के लिए विशेष रूप से इच्छुक है।

जम्मू एवं कश्मीर के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री चन्दर प्रकाश गंगा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को सहायतापूर्ण बर्ताव एवं जम्मू एवं कश्मीर के प्रति मदद के दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, उन्होंने केन्द्रीय मंत्रालय से राज्य के लिए लक्ष्य में भी वृद्धि करने का आग्रह किया, जिससे कि स्थानीय कारीगरों को लाभ पहुंच सके।

केन्द्रीय मंत्री के साथ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना एवं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव श्री के. के. जालान भी थे।

श्रीनगर में नयी पहल

जम्मू-कश्मीर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां

माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

खादी की ऐतिहासिक यात्रा अनवरत जारी है....

हरमुख खादी संस्था, एक आयोग सहायित संस्था, को 25 चरखे उपहार में दिये गये, जो इलाही बाग, बुशपोरा, जिला श्रीनगर में स्थानीय महिलाओं को प्रदान किये।

श्रीनगर में आयोजित एक दिवसीय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यशाला में संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना।

श्रीनगर में जम्मू कश्मीर खादी फेडरेशन के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करते हुए आयोग के अध्यक्ष।

श्रीनगर में नये खादी ग्रामोद्योग बिक्री केन्द्र का शुभारंभ।

स्थानीय उद्योगों के उन्नयन हेतु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर जोर

एमएसएमई मंत्री ने की जम्मू-कश्मीर मुख्य मंत्री से मुलाकात

मई 08, 2016 श्रीनगर: केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने श्रीनगर में अपने प्रवास के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ़्ती से उनके घर पर मुलाकात की और राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यापार को सुगम बनाने से संबन्धित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप में चर्चा की। इस अवसर पर राज्य सरकार के कुटीर उद्योग मंत्री श्री चन्दर प्रकाश, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना एंव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के सचिव श्री के. के. जालन भी उपस्थित थे।

मुख्य मंत्री महोदया ने श्री कलराज मिश्र से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1500 से 4000 तक लक्ष्यांक में वृद्धि करने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया की क्रेडिट-लिंक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हो रही है और लक्ष्यांक में वृद्धि होने से अधिकतर उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में सक्षम होंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने सुश्री महबूबा मुफ्ती को, इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो प्रगति पर है तथा इसके क्रियाशील होने पर इसमें, जम्मू और कश्मीर सहित अन्य क्षेत्रों के भावी उद्यमियों को दक्षता विकास से संबन्धित पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ।

सुश्री महबूबा मुफ्ती ने पी.पी.डी.सी. मेरठ के स्वरूप के अनुसार अनंतनाग में क्रिकेट बैट के निर्माण हेतु प्रोद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के संबंध में मुद्दे उठाए। उन्होंने ''क्लस्टर विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत यह केंद्र स्थापित करने से सम्बंधित जानकारी दी, जिसमें, मूल्य संवर्धन पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे उत्पादक उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट बैट बनाने में समर्थ होंगे।

श्री के.के. जालन ने बैठक में सूचित किया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में 10 प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने पर ध्यान दे रहा है, इसमें से एक केंद्र स्पोर्ट्स क्लस्टर के रूप में अनंतनाग में खोलने पर विचार किया जा सकता है जिसके लिए राज्य सरकार ने जमीन देने का वादा किया है। उन्होंने बैठक में व्यवहार्य कुटीर उद्योगों विशेषकर पौराणिक हस्तशिल्प के उन्नयन के लिए प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संबंध में भी जानकारी प्रदान की।

चर्म उत्पादन क्षेत्र में काफी संभाव्यता है इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री ने लस्सीपोरा में क्लस्टर आधारित उपागम स्थापित करने पर भी विचार किया तथा इसके लिए राज्य सरकार ने सी.एल.आर.आई. (चेन्नई लेदर रिसर्च इंस्टिट्यूट) सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जिससे चर्म उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

महबूबा मुफ्ती ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि ग्रामोद्योग जैसे क्रवेक, सोजनी, नमदा, गब्बा, चैन कढाई, सिल्क रीलिंग, विल्लोंल विक्कर और शहद प्रसंस्करण के लिए 37 क्लस्टरों को तत्काल अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने में सहायता करने हेतु राज्य में इलैक्ट्रोंनिक सेवा और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँगे

जिससे हमारे युवा उद्यमियों के लिए इलैक्ट्रोनिक सामग्रियों और पुर्जो का उत्पादन किया जाएगा।

जम्मू में चावल क्लस्टर एंव श्रीनगर में पेपर-मैशे क्लस्टर स्थापित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बैठक में यह भी सूचित किया गया कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदनो को उपयोग में लाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय कार्यप्रणाली को सरल बना रही है।

मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि पामपोर और जम्मू में मार्केट प्लाजा स्थापित करने की औपचारिक अनुमति प्रदान की जाय, नियमों के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्व में ही इसकी अनुमति प्रदान की है। ई.डी.आई. जम्मू के लिए अतिरिक्त इन्फ्रस्ट्रक्चर का सृजन करने एंव जम्मू और श्रीनगर में महिलाओं के लिए अलग से उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित करने संबंधित मुद्दों पर व्यापक प्रस्ताव केन्द्रीय दक्षता विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाएगा।

श्री कलराज मिश्र ने मुख्य मंत्री से शुभारम्भ की जा रही आधुनिक ई-चरखा पर विचारविमर्श किया, इसके लिए बुनकरों को और विशेष रूप से महिलाओं को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने पशमीना के संबंध में भी कहा कि इसे पूर्व में सू.ल.म.उ. क्षेत्र से बाहर रखा गया था अब इसे इस सूची में शामिल किया गया है।

महबूबा मुफ़्ती ने जम्मू और कश्मीर में स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुन:सृजन करने हेतु योजना निधि) क्षेत्र में विस्तार करने की जरूरत पर प्रकाश डाला, इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक उद्योगों जैसे हाथ-कताई और हाथ-बुनाई एंव विभिन्न किस्म के सिल्क को और अधिक उत्पादक और स्पर्धात्मक बनाना। मुख्य मंत्री ने कहा कि चूंकि जम्मू और कश्मीर की भौगोलिक स्थिति योजनाओं के अनुरूप नहीं है। जम्मू और कश्मीर में एमएसई-सीडीपी योजना के अंतर्गत ''एक जिले के लिए एक औद्योगिक सम्पदा होनी चाहिए।" उन्होंने बताया कि कुछ जिले जैसे श्रीनगर, पुलवामा और बुदगम, कथुआ, सांबा और जम्मू जिला की स्थानीय स्थिति लाभदायी होने से इन जिलों को निवेशकों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है, जम्मू और कश्मीर में इन प्रत्येक जिले में एक से अधिक औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

चूंकि जम्मू और कश्मीर, अन्य राज्यों से भिन्न है इसलिए यह राज्य सू.ल.म.उ. योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह राज्य सू.ल.म.उ. क्षेत्र के विकास के लिए अपनी उचित भागीदारी नहीं दे पा रहा है। उन्होंने मुख्य रुप से 'मुद्रा योजना" के बारे में उल्लेख किया, जिसमें उन उद्यमियों को जो अपनी इकाई की शुरुआत करना चाहते हैं उन्होंने वगैर किसी बाधा के अग्रिम ऋण प्रदान किया जाएगा। मंत्री महोदय ने बताया कि यह निर्णय लिया गया था कि राज्य उद्योग विभाग, मुद्दों को सुलझाने के लिए शीघ्र ही नई दिल्ली का दौरा करेगी ताकि राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की कमियों को दूर किया जा सके और राज्य की अर्थ व्यवस्था में अपना वास्तविक योगदान दे सके।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि

- कलराज मिश्र

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री कालराज मिश्र ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के राष्ट्रीय सम्मेलन (सूक्ष्म, लघु उद्यमों का समूहीकरण - सतत विकास की ओर बढ़ते कदम) का उद्घाटन 10 मई 2016 को नई दिल्ली में किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव, श्री के. के. जालान इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्र ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में अपार संभावनाएं है और देश में रोजगार के अवसरों के सृजन की विशाल क्षमता है। द्रुत गति से विकास की ओर अग्रसर, प्रमुख वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एकीकरण करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 'मेक इन इंडिया' ब्रांड को बाजार देने की संभावना है।

श्री कलराज मिश्र इस दिन क्लस्टर विकास कार्यक्रम का उदघाटन और क्लस्टर विकास की सफलता की कहानी के संक्षिप्त सार-संग्रह ''परचम'' का शुभारंभ कर रहे थे।

श्री कलराज मिश्र ने कहा कि इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागु किया जा रहा है। सॉफ्ट इंटरवेनशन जैसे क्षमता विकास, मार्केटिंग विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा हार्ड इंटरवेन्शन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और नए/ विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों/ क्लस्टरो में इन्फ्रस्ट्रक्चर उन्नयन आदि शामिल है।

देश के 29 राज्यों में एम.एस.ई.- सी.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्लस्टरों में अभी तक कुल 1018 इंटरवेन्शन (डाइगोस्टिक स्टडी, सॉफ्ट इंटरवेन्शन और सामान्य सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए जा रहें हैं इसमें से 1018 इंटरवेन्शन, 677 क्लस्टर पूर्ण किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अंतर्गत 178 इंटरवेन्शनो पर कार्य चल रहा है, इसमें से 126 इंटरवेनशन पूर्ण किए गए हैं।

एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजना ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की उत्पादकता में वृद्धि करने, इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाने और क्षमता विकास करने की रणनीति को प्रमाणित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमो का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उद्यमिता का उन्नयन करना, रोजगार का सृजन करना, उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजना को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और इससे वृहद संख्या में कारीगर लाभान्वित हुए है भारत में एम.एस.ई. क्लस्टरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं तथा इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अपेक्षित सुविधाएं प्रदान किए गए हैं और इसमे अधिकतम वृद्धि करने में एम.एस.ई. समर्थ है।

इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि निवेश सुविधा के माध्यम से क्लस्टर विकास उपागम ने स्थायी अर्थ-व्यस्था का निर्माण, नवीनीकरण, दक्षता विकास में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। भौगोलिक कारणों से भारत में क्लस्टर इकाईयों की सूक्ष्म, लघु उद्यमों के विकास में प्रमुख भूमिका है। भारत के भविष्य निर्माण में क्लस्टर विकास और सम्मिलित विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का स्थायी विकास करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों आदि का मुख्य स्थान है।

बदलते आर्थिक परिदृश्य में क्लस्टर विकास से बिजनेस प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री

यह बुद्धिजीवी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का ऐसा सम्मेलन है जो एक अग्रणी को अनुयायी से अलग करता है और आपके व्यापार को शीर्ष तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।

सम्पूर्ण भारत के उद्यमों के उद्यमी 17 मई, 2016 को सेंट रेगिस होटल, मुंबई में 'आउटलुक बिजनेस स्मार्ट इंटरप्राइस सम्मेलन" में एकत्रित हुए थे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने अपने सम्बोधन में भारतीय युवाओं को दक्षता विकास करने और सुयोगपूर्ण तथा सकारात्मक वातावरण का सृजन करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में कलस्टर विकास के व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और उद्यमिता, रोजगार और आजीविका प्राप्त करने के अवसरों को सृजित किया जाएगा और अनेक उत्पादों वाले क्लस्टरों का विकास करने का प्रयास भी किया जाएगा।

उद्योग आधार ज्ञापन हेतु किए गए पहलों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए पंजीकरण करने हेतु कम से कम जानकारी अपेक्षित है, वास्तविक रूप में उद्यमी बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब व्यक्ति में एक बेहतर योजना बनाने की क्षमता हो और वह दृढ़ निश्चयी हो।

मंत्री जी ने पुन: दोहराया कि हमारी बहुत सी योजनाएँ मांग आधारित और आवश्यकता आधारित है, जो इन्हें उद्यमी अनुकूल बनाता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम–सीडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 108 इंटरवेंशन जैसे डाइग्नोस्टिक अध्ययन, सॉफ्ट इंटरवेंशन, 29 से अधिक जिलों के अंतर्गत विभिन्न कलस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें से 677

कलस्टर पूरे किए गए हैं । इन्फ्रस्ट्रक्चर सुविधा का उन्नयन करने हेतु 178 इंटरवेनशनो का कार्य चल रहा है, इसमें से 126 इंटरवेंशन पूर्ण किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिसका आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में टूल रूम स्थापित करके इन्फ्रस्ट्रकचर के विकास पर ज़ोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का उल्लेख करना नहीं भूल सकते हैं, और सूचित किया कि इस क्षेत्र में लगभग 22 प्रतिशत सामग्रियों का निर्यात एंव 40 प्रतिशत तक उत्पादों की बिक्री की गई तथा 40 प्रतिशत तक बाजार उन्नयन और विकास सहायता की गई। उन्होंने सूक्ष्म, लघु, उद्यमो में सरकारी खरीद पर ज़ोर देते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा 20 प्रतिशत की खरीदी किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने अपने सम्बोधन में स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया का भी उल्लेख किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अपने कठिन परिश्रम से 21वीं सदी के भारत के अद्यौगिकीकरण की पुन: कहानी लिखेगा।

बिजनेस समिट-'पावर ऑफ आई' एक दिवसीय कार्यक्रम में रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु तथा स्टील और खनिज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विभिन्न कार्यवाही जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। व्यापार जगत के गणमान्यों जैसे प्रभात डेरी, माइक्रोमेक्स इंफोर्मेटिक्स, एयरबस इंडिया, ए.बी.बी. इंडिया,

सी.आई.आई.कन्नूर जिला के एम.डी. इत्यादि के प्रबंध निदेशकों साथ पैनल विचार विमर्श किया गया तथा प्रभात डेरी और आई.डी. फ्रेश फूड के मुख्य प्रबंध निदेशकों ने पावर ऑफ आई कंपनियों के संबंध में प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया और आउटलुक पत्रिका के विशेष अंक 'आउटलुक-दि पावर ऑफ आई' के विमोचन पर भी प्रजेंटेशन दिया गया।

वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, मुंबई में डी.बी.टी. पी. पर पी.एम.ई.जी.पी. बैंकर्स समीक्षा बैठक

मुंबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर मेंआयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा डी.बी.टी. पी. पर पी.एम.ई.जी.पी. बैंकर्स समीक्षा बैठक का आयोजन किया।

समीक्षा बैठक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण कुमार झा, वित्तीय सलाहाकर श्रीमती ऊपा सुरेश, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.एम.ई.जी.पी.,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पश्चिम क्षेत्र, निदेशक, आईटी तथा खादी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा बैकरों ने भाग लिया।

हिसार में माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यक्रमों की समीक्षा

श्री कलराज मिश्र, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 मई 2016 को हिसार, हरियाणा का दौरा किया एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र, एम.एस. एम.ई. एवं एन.एस.आई.सी. द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री महोदय के अतिरिक्त श्री मोहन भाई कल्याण भाई कुण्डारिया, माननीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार; डा. कमल गुप्ता, विधायक, हिसार एवं संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार; श्री एस.पी. सिंह, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खा.ग्रा.आ., चण्डीगढ़, श्री वी.के. नागर, राज्य निदेशक, खा.ग्रा.आ., अम्बाला; श्री एस.के. मिश्रा, सहायक निदेशक, राज्य कार्यालय, खा.ग्रा.आ., अम्बाला; श्री मेजर सिंह, निदेशक, एम.एस.एम.ई.; श्री हरीश, प्रतिनिधि, एन.एस.आई.सी., खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारीगण; उद्योग फैडरेशन के प्रतिनिधि व खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं कारीगर उपस्थित थे।

श्री कलराज मिश्र ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों, औद्योगिक फैडरेशन एवं कारीगरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार खादी के उत्थान, विकास एवं सशक्तिकरण के प्रति बड़ी गम्भीरता से कार्य कर रहा है ताकि देश के गांव-गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। खादी में बेरोजगारी मिटाने की शक्ति है, जिसे उनकी सरकार ने पहचाना और खादी के तीव्र विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। वर्तमान सरकार के दो वर्षों के शासन काल में पूरे देश में खादी की बिक्री में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं खादी के विकास हेतु प्रयत्नशील हैं, जिन्होंने समय-समय पर मन की बात एवं अन्य कार्यक्रमों में खादी को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि खादी कारीगरों के कल्याण हेतु अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना व जन-धन योजना आरम्भ की गई है। कारीगरों को उनका भुगतान पारदर्शिता के साथ समय पर प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की गई है कि एवं अब कारीगरों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जायेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी पारदर्शिता लाकर सभी आवेदन ऑनलाइन किये गये हैं, प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि उद्यमियों को शीघ्र ही धनराशि की प्राप्ति हो जाए। ई-ट्रेकिंग के जरिये अब उद्यमी अपने प्रस्ताव की स्थिति को देख सकते हैं। उद्यमियों को मदद देने के लिए एक ई-पोर्टल बनाया गया है, जिसमें उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने बताया किसरकार ने नाम से एक नई योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत इन्क्यूबेशन सेन्टर बनाये जायेंगे और नये उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल में वृद्धि की जायेगी।

उन्होंने आगे कहा कि गत दो वर्षों के शासन काल में सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं अब उनके परिणाम सामने आने लगे हैं। आने वाले वर्षों में विकास की गति और तेज होगी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनके मुख्यालय की ओर से खादी और ग्रामोद्योगी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की काई कमी नहीं होने दी जायेगी।

उन्होंने उपस्थित औद्योगिक फैडरेशन के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि उद्योगों को लगाने व चलाने में किसी प्रकार दिक्कत उद्यमियों को नहीं आने दी जायेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों के सामने बैंक से लोन लेना बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए बैंकों के साथ बैठक की जा रही है। यदि उद्यमी लोन नहीं चुकाता है तो ऐसी स्थिति में उसे डिफाल्टर घोषित किया जाता है। हमारी सरकार ने इस अडचन को दूर करने के लिए एम.एस.एम.ई. एक्ट में सुधार किया है। अब उद्यमी डिफाल्टर होने की स्थिति में बैंक से कह सकेगा कि वह अपने निर्णय पर पुर्नविचार करें। उद्योगों से सम्बन्धित प्रकरणों का जल्द निपटारा करने के लिए सरकार ने कमर्शियल कोर्ट खोलने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एन.एस.आई.सी., एम.एस.एम.ई. के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ कारीगरों तक पहुंच सके।

इससे पहले, आयोग के राज्य निदेशक, अम्बाला श्री वी.के. नागर ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि हरियाणा राज्य में खादी की 100 संस्थाएं हैं जो लगभग 105 करोड़ रूपये मूल्य की खादी का प्रतिवर्ष उत्पादन करती हैं। राज्य में 223 खादी ग्रामोद्योगी भण्डार हैं। इन खादी संस्थाओं के साथ 34 हजार से अधिक कारीगर जुड़े हैं जिनमें कत्तिन एवं बुनकर शामिल हैं। खादी उत्पादन, बिक्री एवं कारीगरों की आमदनी बढ़ाने हेतु अनेकों कदम उठाये गये हैं, जिनमें नये चरखे एवं करघों की खरीद करना, नये कत्तिनों एवं बुनकरों को प्रशिक्षण देना, नये खादी भण्डार खोलना, पुराने भण्डारों का नवीनीकरण करना, आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त करना, खादी कपड़े के अलावा नये नये डिजाईनों के रेडिमेड वस्त्रों का निर्माण करना, जो इकाईयां गत कई वर्षो से किन्ही कारणों से बन्द थी उनके पुर्नजीवन के लिए प्रयास करना, कत्तिन एवं बुनकरों को कार्य करने में आसानी हो अत: उनको स्वयं की कार्यशाला निर्माण करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, खादी संस्थाओं को विपणन के क्षेत्र मदद देने के लिए उन्हें घरेलू और अन्तर राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर देना, कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उन्हे आम आदमी बीमा योजना के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित अटल पैंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ देना, सभी खादी स्टोर को एकरूप देना, खादी को एक ब्रांड के रूप मे स्थापित करना एवं खादी के साथ युवाओं को जोड़ना, कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए खादी कारीगरों के भुगतान को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करना, खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की अधिक से अधिक खादी संस्थाओं को जोड़ना, रिवैम्पड स्फूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नये कलस्टर स्थापित करना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित करना आदि शामिल है।

श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुण्डारिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि हरियाणा प्रदेश अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में औद्योगिक विकास का नया वातावरण बना है एवं रोजगार के नये-नये रास्त खुले हैं। उन्होंने बताया कि अभी तो केन्द्र सरकार को केवल दो वर्ष पूरे हुए हैं एवं उन दो वर्षों के भीतर सभी योजनाओं में गति आयी है।

दिनांक 26 मई, 2016 को आयोग मुख्यालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 633वीं बैठक, आयोग के अध्यक्ष के श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एवं एमएसएमई के संयुक्त सचिव श्री अनिल कुमार तथा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण कुमार झा की उपस्थिति में संपन्न हुई।

केन्द्रीय ऊर्जा एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सेवापुरी, वाराणसी का दौरा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण कुमार झा के मार्गदर्शन में माननीय उर्जा और कोयला मंत्री, श्री पीयूष गोयल; संयुक्त सचिव उर्जा, कौशल विकास; संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्किल इंडिया, श्री सुनील ओझा, अध्यक्ष, टाटा समूह और प्रधानमंत्री कार्यालय से श्री तन्मय के एक प्रतिनिधिमंडल ने सेवापुरी, वाराणसी का दौरा किया।

1949 में स्थापित, सेवापुरी, वाराणसी में चमड़े के उत्पाद, साबुन, अगरबत्ती के अतिरिक्त सूत कताई का काम भी होता है। पिछले 8 दशकों से यहाँ के उत्पादन में काफी गिरावट आई है। गणमान्य व्यक्तियों के इस दौरे से इस केंद्र के उत्थान में वृद्धि होगी। माननीय उर्जा और कोयला मंत्री और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने निष्क्रिय और दयनीय स्थिति वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की विकास संभावनाओं पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी के जयापुर ग्राम का भी दौरा किया जहाँ उन्होंने महिला कत्तिनों से बातचीत की और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ 25 से अधिक परिवारों को न्यू मॉडल चरखा के माध्यम से और लगभग 5 परिवारों को ग्राम लक्ष्मी करघा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा इस गांव में स्व रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए करीब 10 लोगो को सिलाई मशीनों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

रामभाऊ म्हलगी प्रबोधिनी में आयोग के सहयोग से विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के साथ विचार विमर्श हेतु सेमिनार

खादी और ग्रामोद्योग आधारित उद्योगों को विकासशील बनाना है

मुंबई, 1 जून 2016: रामभाऊ म्हलगी प्रबोधिनी (आर.एम.पी.), जो की एक कल्याणकारी संगठन है, ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के साथ विचार विमर्श हेतु सेमिनार का मुंबई के उपनगर भायंदर, उत्तन स्थित केशव कुटीर में आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय था "भारत में खादी और ग्रामोद्योग आधारित उद्योगों को विकासशील बनाना और इनका उन्नयन करना।" आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उदघाटन किया। श्री अशोक भगत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विशेषज्ञ सदस्य, श्री रवीद्र साठे, कार्यकारी निदेशक, आर.एम.पी. भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने उदघाटन सम्बोधन में गैर-सरकारी संगठनों के मूल-भूत उद्देश्य को समझने की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गैर-सरकारी संगठनों को अभी तक मात्र व्यवधानों के लिए जाना जाता है। इस धारणा में परिवर्तन लाने की जरूरत है और देश की ग्रामीण जनता को सहयोग देने पर ध्यान देने की जरूरत है। श्री सक्सेना ने उपस्थित संगठनों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में आयोग की ओर से हर संभव सहायता प्रदान देने पर बल दिया।

पूर्व में श्री रविन्द्र साठे, कार्यकारी निदेशक, आर.एम.पी. ने सभी भागार्थियों का स्वागत किया और उन्हें इस बात से अवगत कराया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य एक क्षेत्र में

स्थित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठन जो आर.एम.पी. से जुड़े हैं को एक साथ एक मंच पर लाना, ये संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ किए गए विचार विमर्श से लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर श्री एम.राजन बाबु, निदेशक, प्रचार और सूचना प्रौद्योगिकी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आयोग के नवीनीकृत स्फूर्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण में स्फूर्ति कार्यक्रम की शुभारंभ से क्लस्टर विकास के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्फूर्ति कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में भी विचार-विमर्श किया। निदेशक महोदय ने दृढ़तापूर्वक कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस योजना के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में 800 क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्यांक निर्धारित किया है। उन्होंने इस पर भी ज़ोर दिया कि नवीनीकृत स्फूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केवल गैर-कृषि क्षेत्र ही योग्य हैं। उन्होंने, स्फूर्ति कार्यक्रम में राज्य सरकार, तकनीकी एजेंसियों और नोडल एजेंसियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ऑनलाइन इंटरफेज भी प्रदर्शित किया जिसका उपयोग स्वैच्छिक संगठन फॉर्म भरने के लिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं।

आयोग के जैव प्रौद्योगिकी/ ग्रामीण आभियांत्रिकी उद्योग के निदेशक श्री बी.एस. माने ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008-09 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और अब तब 32.84 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने अपने प्रजेंटेशन में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एंव साथ में वृहद उद्योगों के संबंध में जिन्हें 2015-16 में आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई के बारे में वर्ष-वार जानकारी दी। इसके अतिरिक्त भागार्थियों को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित उत्पादों और उनके संवर्ग के बारे में जानकारी दी। श्री माने ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए विभिन्न नई पहलों के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने दर्शकों द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन करने के संबंध में किए गए विभिन्न शिकायतों के बारे में भी सम्बोधन किया और उन्होंने स्वैच्छिक संगठनों को यह भी आश्वासन दिया कि आयोग सुधार की आवश्यकता को भलीभांति समझता है।

श्री बी.एस. माने ने ही भारत के विभिन्न भाग में स्थित मधुमक्खीपालन उद्योग के कार्य और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने प्रस्तुति के माध्यम से दिखाया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एशिया में मात्र एक ऐसा संस्थान हैं जो शहद की खरीदी और बिक्री करता है। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों और मधुमक्खीपालन की विभिन्न तकनीको के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मधुमक्खीपालन उद्योग के संबंध में विचारविमर्श करने के अलावा मधुमक्खीपालन के लाभ और उसके विशेषताओं के संबंध में जानकारी दी। श्री माने ने मधुमक्खीपालन करने में डाटा एकत्रण करने, अनुसंधान करने तथा मधुमक्खीपालन प्रौधोगिकी के प्रचार और प्रसार करने में आयोग की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार के पौध-रौपण पर भी सभी का ध्यान केन्द्रित कराया। उन्होंने प्रकृतिक स्वास्थ्यवर्धक पेय नीरा के बारे में विचार विमर्श किया और बताया कि इसके माध्यम से देश में वास्तविक रूप में रोजगार का सृजन किया जा सकता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहायक निदेशक प्रभारी डॉ. एस. ग्रीप ने सोलर चरखा को उपयोग में लाने और इसके लाभ के संबंध प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सोलर चरखा के कुल लागत और इसकी क्षमता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने दर्शकों को यह बताया

कि 16 तकुए के चरखे की कुल लागत लगभग 70,000 रूपये से 1.00 लाख रूपये तक है तथा इससे प्रतिदिन 4.5 कि.ग्रा. सूत का उत्पादन होता है। श्री ग्रीप ने आगे बताया किया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वस्त्र उद्योग में खादी के शेयर को 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है।

प्रश्नोत्तर सत्र में, श्री एस.बी. माने एंव श्री एम. राजन बाबु ने भागार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रतिभागियों ने सुविधा देने और गैर सरकारी संगठनों को मार्ग निर्देशन देने के संबंध में भी प्रश्न पूछे। उन्होंने लोगों को यह भी जानकारी दी कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कार्यालय स्थित है। श्री राजन बाबू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वैच्छिक संगठन को चाहिए कि वे कारीगरों को प्रत्यक्ष सहयोग दें। उन्होंने आगे यह भी कहा कि स्वैच्छिक संगठनो को उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभग्राही बनने के लिए सक्षम होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि स्वैच्छिक संगठनों को कारीगरों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों को दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अशिक्षित ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। अंत में श्री बाबू ने सुझाव दिया कि स्वैच्छिक संगठनों को शिकायत करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट को उपयोग में लाना चाहिए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किसी भी विशेष शिकायत के लिए श्री एस.एस. तांबे, उप निदेशक, खा.ग्रा.आ. से संपर्क कर सकते हैं।

आयोग के विशेष सदस्य श्री अशोक भगत ने सभा को अंत में सम्बोधित करते हुए स्वैच्छिक संगठनों से अधिक प्रयास करने के लिए अनुरोध किया और कहा कि उन्हें सकारात्मक विचारधारा को अपनाना चाहिए और स्वैच्छिक संगठनों को सीधे ही आयोग के क्षेत्रीय निदेशकों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को प्रतिभागियों के बीच बांटा।

उपर्युक्त विचारविमर्श करने के पश्चात श्री संतोष गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आई.एस.आर.एन. ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्रामीण जनता के लिए कार्य करने के लिए और उनके दक्षता का विकास करने हेतु स्वैच्छिक संगठनो की जरूरत है। उन्होने आगे स्वैच्छिक संगठनों को ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट आदि के साथ टाई-अप कर विकसित हो रही ई-मार्केटिंग को उपयोग में लाने का सुझाव दिया। श्री गुप्ता ने आई.एस.आर.एन. के संबंध में भी विचार-विमर्श किया।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा न्यायिक मामलों से सम्बंधित पुस्तिका का लोकार्पण एवं ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ

मुंबई, 5 मई, 2016: खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा आज आयोग के न्यायिक मामलो से सम्बंधित एक पुस्तिका का लोकार्पण एवं आयोग के चल रहे मुकद्दमो हेतु ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय मुंबई में किया गया। इस अवसर पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण कुमार झा, वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सभी उपस्थितो को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने दोहराया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को चल रहे न्यायिक मुकद्दमो को न्यायालय के बाहर ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे समय, धन और ऐसी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बचा जा सके।

आयोग के विधि विभाग की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने में बहुत सहायक होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष से हमारा प्रयास अदालती मामलों को शून्य स्तर तक कम करने का होगा।

माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खादी की बिक्री में बढ़ोतरी

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खादी विक्रय केन्द्रों में खादी की खरीद में काफी वृद्धि हुई है। हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों से खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की 37,935 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गयी है।

मुंबई पश्चिमी उपनगर में नवीनीकृत बिक्री केंद्र का उद्घाटन:

मुंबई पश्चिमी उपनगर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 31 मई 2016 को विरल अपार्टमेंट, एसवी रोड, अंधेरी (पश्चिम) स्थित खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के नवीनीकृत बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया।

यहाँ खादी टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, ग्रामोद्योगो के हर्बल और प्राकृतिक उत्पाद तथा साथ ही पारंपरिक खादी उत्पाद भी उपलब्ध है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण कुमार झा, और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थिति थे।

विभागीय बिक्री केन्द्रों के नवीनीकृत हेतु समीक्षा बैठक:

इसके पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय बिक्री केन्द्रों को नवीनीकृत करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण कुमार झा और वित्त सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश उपस्थित थे।

इस अवसर पर सभी विभागीय बिक्री केन्द्रों के प्रबन्धकों ने खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री में बढ़ौतरी करने हेतु बिक्री केन्द्रों को नवीनीकृत कर आकर्षक बनाने के लिए एक

वृहद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बैठक में उत्पादों की बारकोडिंग, बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण, स्थापना खर्च में कमी, पैकेजिंग व्यवस्था में सुधार, आवधिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सारणी, सेल्समैन/सेल्सगर्ल के लिए वर्दी, उत्पादों के डिजाइनों को आधुनिक बनाना और उत्पादों का विज्ञापन देने हेतु निम्नतम लागत पर व्यावसायिकों को कार्यरत्त करना, बिक्री केन्द्रों के लक्ष्याकों की तिमाही मोनीटरिंग, विभागीय बिक्री केन्द्रो के मध्य संमिलन, त्योहारों और छुट्टियों पर विशेष छूट, भवनों में सी.सी.टी.वी. की स्थापना, गोदामों और भवनों को कम्प्यूटरीकृत करना, नामपट्ट लगाने इत्यादि पर निर्णय लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने तीन महीने के पश्चात समीक्षा बैठक की व्यवस्था करने का निदेश दिया।

अन्त में, धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश में संचालित की जा रही खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों की समीक्षा

अध्यक्ष महोदय ने कहा, एक गांव को गोद लें

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और सदस्य (मध्य क्षेत्र) ने 14 से 17 मई 2016 तक मध्यप्रदेश राज्य का दौरा किया।

दिनांक 15.05.2016 को पीएमईजीपी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें अध्यक्ष महोदय, सदस्य (मध्य क्षेत्र), आयोग के अधिकारियों तथा बैंकों के राज्य स्तरीय समिति के संयोजक, श्री अजय व्यास, श्री डी. पी. शर्मा, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ इंडिया एवं वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ़ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया इत्यादि में भाग लिया।

खादी संस्थाओं के साथ आयोजित एक बैठक में समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रदेश में खादी के कार्यक्रम आशा के अनुरूप संपन्न नहीं हो पा रहा है। इस बारे में संस्थाओं ने बताया कि धन के अभाव के कारण कार्यक्रम के विकास में बाधा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संस्थाएं, के.पू.स., सीहोर तथा राज्य कार्यालय एक सामूहिक बैठक करके वस्तुस्थिति का निर्धारण करते हुए यह बताये कि संस्थाओं को लक्ष्यांको के सापेक्ष उन्हें कितने कच्चे माल की आवश्यकता है और उनके ऊपर आयोग का ऋण भार कितना है।

अध्यक्ष महोदय ने उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी तथा आयोग के सिहोर स्थित केन्द्रीय पूनी संयंत्र का भी अवलोकन किया। दिनांक 16.05.2016 को माननीय अध्यक्ष ने औंकारेश्वर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की गरीबी, पिछड़ेपन एवं आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए क्षेत्र के विकास में खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों का सघन संचालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने, क्षेत्र के सघन विकास के लिए सभी से एक गांव गोद लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पी.एम.ई.जी.पी. कार्यक्रम, सीधे लाभ हस्तांतरण करने में अधिकतम पारदर्शिता ला रहा है

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नोडल अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए सर एस. पोचखनवाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज मुंबई में 5से 6 मई, 2016 को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सीधे लाभ हस्तांतरण पर पूर्वाभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर दो दिवशीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण झा ने अपने उद्घाटन सम्बोधन में कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नोडल अधिकारियों की पूरी ज़िम्मेदारी इस प्रमुख योजना को सफल बनाने की है और उन्हें इस योजना में अपना शत प्रतिशत योगदान देना होगा। इसका नियंत्रण खादी और ग्रामोद्योग आयोग एंव डी.आर.पी.एस.सी. के पास होना चाहिए। यह एक ऐसी योजना है जो साकारात्मक पर्यावरण का सृजन करेगी।

उन्होंने, (डी.बी.टी.) सीधे लाभ हस्तांतरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आवेदन करने के लिए ऑन-लाइन व्यवस्था निरंतर जारी रखी जाएगी। इस व्यवस्था के माध्यम से एक बेहतर ट्रेक रिकॉर्ड होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रोजेक्ट स्थापित करने से पूर्व उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए, इससे प्रोजेक्ट में तेजी लाने की और इसे कैसे सफल बनाया जाए इसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त निधि जारी करने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष दबाव भी होगा। यहाँ पर नोडल अधिकारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने इस अवसर पर पेपर रहित कार्य और डिजिटल कार्य करने पर दबाव डाला, यह ई-मेल, अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से भी किया जा सकता है जिससे परिणाम तत्काल निकलेगा।

वित्त सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश ने अपने सम्बोधन में पुन: दुहराते हुए कहा कि सीधे लाभ हस्तांतरण में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी क्योंकि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जानकारी ऑन

लाइन प्राप्त की जा सकती है। यह एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सहायक होगा तथापि इस प्रणाली से ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की ज़िम्मेदारी से नोडल अधिकारियों के माध्यम से कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और परिणाम भी बेहतर निकलेगें।

पूर्व में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस. राव ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की सफलता के अनुपात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 80 प्रतिशत प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट है। नोडल अधिकारियों के श्रेयनीय प्रयासों से इकाइयों की सफलता संभव हो पायी है।

उन्होंने नोडल बैंक अर्थात कोर्पोरेशन बैंक के कार्यों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि यह बैंक निधियों और मार्जिन मनि का संवितरण द्रुत गति से करती है। उन्होंने लाभग्राहियों के आवेदनों को स्वीकृत करने से पूर्व उद्यमीता विकास कार्यक्रम में भाग लेने पर बल दिया। इससे उनके आत्मविश्वास और विश्वास में वृद्धि होगी।

पूर्व में, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना निदेशालय की निदेशक, श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर, ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से मूल स्तर पर 80 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने प्रधान

मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संशोधित दिशानिर्देशन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी और इस योजना को सफल बनाने हेतु भागार्थियों को प्रोत्साहित किया।

सत्र के मध्य में भागार्थियों को प्रपत्र भरने के बारे में जानकारी दी गयी तथा उनके संदेहों का निराकरण किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक श्री राजन बाबु ने प्रेजेंटेशन दिया तथा इसके माध्यम से हिन्दी और अँग्रेजी में प्रपत्र कैसे भरने है इस संबंध में जानकारी दी। श्रीमती पिंकी भरतीया, अर्थ अधिकारी ने एम.आई.एस. का डी.बी.टी. लिंक के माध्यम से भगार्थियों को जानकारी प्रदान की।

कार्यशाला के अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वित्त सलाहकर ने सभी भागार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

इसके पश्चात अंत में श्री एस.जी. राऊत ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रगति के राह पर

एयर इंडिया का दूसरा बड़ा ऑर्डर

एयर इंडिया ने पहले ही अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्राकृतिक और पर्यावरणनुकूल खादी के उत्पादों को उपयोग में लाने का निर्णय लिया है तथा एयर इंडिया ने 1,85,000 किटों की आपूर्ति करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के समक्ष लगभग 8 करोड़ रु. का दूसरा ऑर्डर प्रस्तुत किया है।

पूर्व में, दिसंबर 2015 में एयर इंडिया ने 25,000 अमेनिटी किटों की आपूर्ति करने हेतु लगभग 1.21 करोड़ रु. का ट्रायल ऑर्डर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसकी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 40 दिनों के निर्धारित समय के अंदर सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई था।

एयर इंडिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रथम श्रेणी और बिजनेस श्रेणी के यात्रियों को अमेनिटी किट प्रदान किए। इस किट में खादी हैण्ड सैनिटाइजर, खादी मॉइश्चराइजर, लोशन, लेमनग्रास खादी साबुन, खादी लिप बाम, खादी रोज फेशवॉश, सुगंधित तेल इत्यादि सामग्रियाँ शामिल की गई थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग 4 माह के निर्धारित समय में एयर इंडिया को 1,85,000 किटों की आपूर्ति करेंगा, इसमें से प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए 6000 किट और बिजनेस श्रेणी के यात्रियों के लिए 1,79,000 किटों की आपूर्ति करेगा। इस ऑर्डर के लिए 4,40,000 घंटे कार्य करने की जरूरत होगी इस ऑर्डर संबन्धित कार्य को पूरा करने के लिए कारीगरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने यह जानकारी दी कि भारत के प्रधान मंत्री ने अपनी ''मन की बात'' के माध्यम से खादी के कम से कम एक उत्पाद की खरीदी करके ग्रामीण कारीगरों को सहयोग देने की जनता से अपील की है, इससे खादी की बिक्री में बहुमुखी वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक लोगों विशेष रूप से युवाओं तथा किशोरों ने खादी की खरीदी की है। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2014-15 में 1,170 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2015-16 में खादी के उत्पादों की 1,510 करोड़ रु. तक बिक्री हुई अर्थात 29 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मार्केटिंग में पहल करते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खादी उत्सव का आयोजन कर समर क्लक्शन की शुरुवात की है। इसमें ऋतु बेरी द्वारा डिजाइन किये हुए डिजाइनर वियर जैसे खादी डेनिम, जींस, जाकेट्स, टी-शर्ट्स इत्यादि शामिल है।

श्री सक्सेना ने यह भी सूचित किया कि विगत सप्ताह में मुंबई में स्थित अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक नया खादी इंडिया बिक्री केंद्र खोला गया है और एक केंद्र विशाखापटनम एयरपोर्ट में, एक केंद्र लखनऊ में, एक केंद्र जयपुर में और एक केंद्र चेन्नई में तत्काल खोले जाएंगे। अन्य शहरों में 12 फ्रैंचाइज़ी बिक्री केंद्र खोले जाएंगे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की सरकारी आपूर्तियों में वृद्धि करने तथा इन उत्पादों का निर्यात करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि श्रीनगर में राष्ट्र स्तरीय खादी की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उदघाटन 8 मई 2016 को किया गया था, 2 जून तक 1.40 करोड़ रु. की बिक्री पंजीकृत की गई है जो अपने आपमें एक रिकॉर्ड है।

उज्जैन में कुम्भ मेला के दौरान खादी बाजार सिंहस्थ-2016 आयोजित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल द्वारा सिंहस्थ कुम्भ मेला 2016, उज्जैन में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की प्रदर्शनी 'खादी उत्सव 2016" का शुभारम्भ, बड़नगर रोड़, उज्जैन में दिनांक 28.04.2016 को किया गया।

प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री माखन सिंह, अध्यक्ष, सिंहस्थ केन्द्रीय समिति उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री पारसचन्द जैन, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री मोहन यादव, विधायक, उज्जैन के अतिरिक्त श्री सत्यनारायण पवार, पूर्व सांसद एवं श्री प्रेम नारायण नागर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अपने उद्बोधन में श्री माखन सिंह ने कहा कि खादी को जन-जन तक पहुंचाना है एवं उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के उस आह्वान का भी जिक्र किया कि प्रत्येक व्यक्ति को खादी का एक वस्त्र आवश्यक रुप से खरीदना चाहिये, जिससे गरीब कत्तिनों को रोजगार प्राप्त हो सके।

श्री पारसचंद जैन, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन ने अपने उद्बोधन में कहा कि उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ के इस शुभ अवसर पर खादी प्रदर्शनी आयोजन सिंहस्थ कार्यक्रम को और चार-चांद लगा देता है और आशा व्यक्त की कि इस प्रदर्शनी में साधु सन्तों समेत प्रदेश की जनता अधिक से अधिक खादी वस्त्रों का लाभ उठा सकेगी। इसके अतिरिक्त श्री मोहन यादव, विधायक, श्री प्रेम नारायण जी नागर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री सत्यनारायण पवार, पूर्व सांसद ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम के अन्त में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक, भोपाल श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता ने आयोग द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी एवं वर्तमान युग में खादी के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किये तथा प्रदर्शनी को सफल बनाने हेतु सभी से अनुरोध किया।

मथुरा में आयोग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

सोलर पैनल इंस्टालेशन ट्रेनिंग

दिनांक 09.05.2016 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति, दीन दयाल धाम, ग्राम फरहा, जिला मथुरा (उ.प्र.) में आयोग के सदस्य (मध्य क्षेत्र), श्री जय प्रकाश तोमर की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मेरठ के अन्तर्गत कार्यरत चौधरी चरण सिंह बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, जिला शामली द्वारा आयोजित एक 'सोलर पैनल इंस्टालेशन ट्रेनिंग" जो कि दिनांक 03.05.2016 से 09.05.2016 तक आयोजित की गयी थी, का समापन एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन आयोग के सदस्य श्री जय प्रकाश तोमर की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर श्री पदम सिंह, निदेशक, दीन दयाल धाम, फरहा, श्री गुलाम हुसैन, निदेशक, मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मेरठ, श्री राम सिंह, प्राचार्य, एम.डी.टी.सी., पंजोखेरा, अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं आयोग में कार्यरत तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।

उक्त प्रशिक्षण में 28 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। इन सभी प्रशिक्षार्थियों को आयोग के सदस्य के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये गये एवं सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर श्री जय प्रकाश तोमर ने प्रशिक्षार्थियों को मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं आयोग द्वारा संचालित पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर श्री गुलाम हुसैन, निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति, दीन दयाल धाम, ग्राम फरहा, जिला मथुरा (उ.प्र.) को शीघ्र ही आयोग द्वारा गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है एवं फिर यहां पर पूरे वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

इसके बाद माननीय श्री जय प्रकाश तोमर द्वारा दीन दयाल धाम, फरहा द्वारा संचालित 'कामधेनु गौशाला" का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर श्री तोमर के दिशा निर्देशों एवं पहल पर पूर्व में निर्मित एवं अक्रियाशील पड़े दो 3 घनमीटर के दीन बंधु बायो गैस संयंत्रों को आयोग के बी.टी. अनुभाग की देख रेख में तकनीकी मार्गदर्शन देकर पुन: क्रियाशील किया गया। इन दोनों संयंत्रों से कार्यरत बायो गैस बर्नर एवं बायो गैस लैम्प्स का भी क्रियाशील स्थिति में निरीक्षण किया गया एवं कार्य पर संतोष व्यक्त किया गया।

आयोग ने सरकार से "मधुमक्खी" को राष्ट्रीय कीट के रूप में घोषित करने का किया अनुरोध

शहद निष्कासित करने हेतु अहिंसा प्रणाली को अपनाने पर जोर

आयोग ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से, मधुमक्खी को राष्ट्रीय कीट घोषित करने तथा सम्पूर्ण देश में शहद निष्कासन की पारंपरिक प्रणाली जिसमें वनों में मधुमक्खी के छत्तों को धुआं लगाकर एंव उन्हें काटकर शहद निकाला जाता है, की प्रणाली को समाप्त करने का अनुरोध किया।

वर्तमान में मधुमक्खी पालन बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है फिर भी आज भारत में 70 प्रतिशत शहद का उत्पादन जंगली मधुमक्खीयों अर्थात 'रॉक मधुमक्खियों" से होता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को लिखे गए पत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने उल्लेख किया है कि रॉक मधुमक्खियों के प्रत्येक छत्ते में एक लाख से अधिक मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों मधुमक्खी छत्ते नष्ट होते जा रहे हैं और इस प्रकार मधुमक्खियाँ द्रुत गति से विलुप्त हो रही हैं।

रॉक मधुमक्खियों के विलुप्त होने के कारण छोटे जंगलों का भी विलोपन होता जा रहा है। जंगल की जैव-विविधता इन मधुमक्खियों के कारण ही बनी रहती है। द्रुत गति से समृद्ध जैव-विविधता और दुर्लभ जाति के पौधे समाप्त हो रहे हैं। ये गैर-पालतू उग्र रॉक मधुमक्खियाँ विभिन्न जंगली फूलों से परागकण एकत्रित कर रसायन मुक्त और प्रदुषणमुक्त, उत्कृष्ट गुणवता वाले जैव शहद का उत्पादन करती हैं। रॉक मधुमक्खियों को समूहिक रूप में नष्ट होने से बचाने का यह सही समय है, यह मधुमक्खियाँ शहद और मोम का स्रोत, जंगल की रक्षक, फल-फूल और सब्जी के पौधे की परागणकर्ता; उत्कृष्ट गुणवता के बीजों की उत्पादनकर्ता, जैव-विविधता की उद्धारक, दुर्लभ पौधों की जातियों को बचाने वाली इत्यादि की मूल्यवान स्त्रोत हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1938 में वर्धा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ द्वारा विकसित अहिंसा प्रणाली का अनुपालन करने के लिए शहद शिकारियों (शहद निष्कासित करने वालों) को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इस प्रणाली के अंतर्गत रॉक मधुमक्खियाँ अतिरिक्त शहद का भंडारण छत्ते के सबसे ऊपरी हिस्से में करती हैं और यह छत्ते विशेषकर वृक्ष के सबसे उपरी डाल पर स्थित होते है तथा वहाँ पर छत्ते की दिवार उभरी हुई होती हैं जो दूर से दिखाई देती है। छत्ते के जिस भाग में शहद एकत्रित किया जाता है, केवल उसी भाग को काटने की जरूरत है छत्ते के बाकी भाग को नुकसान किए वगैर इसमें मधुमक्खीपालन किया जा सकता है। अत: छत्ते में धुआं लगाने तथा उसे काटने की जरूरत नहीं है।

मधुमक्खीपालकों द्वारा मधुमक्खी छत्ते से शहद रात्री के समय निकाला जाता है उस समय मधुमक्खियाँ शांत रहती हैं। शहद निकालते समय शहद निष्कासित करने वालों को कैन्वास के मोटे कपड़े के सुरक्षित वस्त्र और साथ में सर और चेहरे के लिए सुरक्षा कवच धारण करना चाहिए। शहद निष्कासित करने के लिए केवल तीन उपकरणों की जरूरत है - चढ़ने के लिए

रस्सी, शहद बल्ब को काटने के लिए चाकू और शहद एकत्रित करने के लिए बाल्टी।

इस प्रणाली को अपनाने से बहुत बड़ा लाभ यह है कि एक छत्ते से एक बार ही शहद निकालने के बजाय उसी छत्ते से तीन बार शहद निकाला जा सकता है, वो भी शहद उत्पादन में बाधा डाले वगैर अथवा मधुमक्खी कॉलोनियों के जीवन को अस्तव्यस्त किए वगैर एक सप्ताह के अंदर ही कठिन परिश्रमी रॉक मधुमक्खियां, छत्ते को पुन: बना लेती हैं और पहले से अधिक शहद एकत्रित करती हैं। अत: प्रत्येक फसल में मधुमक्खीपालक दो से तीन गुना तक अतिरिक्त शहद प्राप्त करते हैं।

सरकार सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में 'शहद घर' स्थापित कर सकती है, वहाँ पर शहद एकत्रित करके प्रसंस्करण किया जा सकता है और स्वच्छ पैकेट में पैक किया जा सकता है. इस प्रणाली को गांधी जी के दिशानिर्देशन में विकसित किया गया था। इस प्रणाली के माध्यम से केवल मधुमक्खियों की जीवनरक्षा ही नहीं की जा सकती है बल्कि मधुमक्खीपालकों को चोट लगने, दुर्घटना होने तथा मृत्यु होने से भी बचाया जा सकता है।

उन्होंने आगे यह भी बताया कि भारत के पास में लगभग 120 मिलियन मधुमक्खी कोलॉनियां स्थापित करने की संभाव्यता है, इससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में 6 मिलियन से अधिक लोगों को स्व रोजगार स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इन मधुमक्खियों से 1.2 मिलियन टन शहद और 15,000 टन मधुमक्खी वेक्स का उत्पादन हो सकता है। इस प्रणाली को उपयोग में लाने से 120,000 टन अतिरिक्त और 10,000 टन अतिरिक्त मधुमक्खी वेक्स का उत्पादन हो सकता है। इससे लगभग 2 मिलियन जन जातीय परिवारों का पालन पोषण हो सकता है।

श्री सक्सेना ने कहा कि देश में विभिन्न प्रोजेक्टों के विकास के बावजूद भी मधुमक्खीपालन उद्योग प्रभावित हुआ है, इसका मुख्य कारण है जंगलों का विनाश और जंगलों की कटाई तथा जंगल में आग लगना, शहद निष्कासन हेतु हिंसात्मक पद्धति को उपयोग में लाना तथा शहरीकरण। मधुमक्खीपालन उद्योग की क्षय होती पद्धति की जांच करना आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और जनजातीय जनता जंगल पर निर्भर हैं। यह उनके आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना जरूरी है।

उन्होंने इस पर आगे कहा कि व्यापक रूप में वनरोपण करने से एंव मधुमक्खी को राष्ट्रीय कीट घोषित करने से यह समस्या हल हो सकती है और हिंसात्मक प्रणाली से शहद निकालने की विधि को रोका जा सकता है तथा यह प्रणाली दंडनीय होनी चाहिए।उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि ''भारत हरित क्रांति और सफेद क्रांति का साक्षी है।अब स्वर्ण क्रांति के साक्षी होने का समय आ गया है, जो दूसरी हरित क्रांति वापस ला सकता है।'"

खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि

आर्थिक विकास की गति धीमी होने पर भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है ।

2015-16 के अंतिम आंकलन के आधार पर खादी उत्पादों की 1,510 करोड़ रु. की बिक्री अर्थात 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान 1,170.38 करोड़ की बिक्री हुई थी।

वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक की अवधि में 8.26 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई है. आयोग के प्रत्यक्ष कार्यनिष्पादन के बारे में बताते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आयोग के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई ।

ग्रामोद्योगी क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 36,425 करोड़ रुपये जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान 31,965 करोड़ रु. की बिक्री अर्थात 13.95प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 के मध्य 6.29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। (2013-14 में 30,073 करोड़ रुपये की बिक्री हुई)।

खादी उत्पादों की बिक्री के साथ खादी उत्पादन में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। खादी क्षेत्र में उत्पादन में वर्ष 2014-15 के दौरान 879.98 करोड़ रुपये अर्थात 21 प्रतिशत विकास दर जिसकी तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान 1,065 करोड़ रूपये उत्पादन दर्ज किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 811.08 करोड़ रुपये का उत्पादन पंजीकृत किया है।

ग्रामोद्योगी उत्पादों के उत्पादन में भी वृद्धि देखी जा सकती है। उत्पादन क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान लगभग 26,965 करोड़ रु. का उत्पादन जब कि वर्ष 2014-15 में 26,689 करोड़ रु. का उत्पादन दर्ज किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 25,298 करोड़ रूपये का उत्पादन दर्ज किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2015-16 के दौरान रोजगार में 3.59 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 1.39 करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं। जब कि इसकी तुलना में 2014-15 के दौरान 1.34 व्यक्ति कार्यरत थे। यह ग्रामोद्योगी क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि को दिखाता है। इस क्षेत्र में कारीगरों की संख्या में 2014-15 में 1.23 करोड़ से 2015-16 में 1.28 करोड़ की वृद्धि हुई है।

आईटीडीसी के होटल में दिखेगा खादी का उपयोग

नई दिल्ली, 15 मई, 2016: केंद्र सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है। प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के अधिकारिक विमान एयर इंडिया वन के चालक दल ने खादी को अपनी पसंद बनाया। इससे प्रेरणा लेते हुए पर्यटन मंत्रालय ने अपने आईटीडीसी होटलों में स्वदेशी खादी के प्रयोग का मन बना लिया है। मंत्रालय ने खादी के बढ़ावे के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा बनाए गए कपड़ों को अलग-अलग विभागों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का फैसला किया है।

सरकार के सहयोग से ही मिलेगा खादी को बढ़ावा सूत्रों के मुताबिक आईटीडीसी खादी ग्रोमोद्योग द्वारा तैयार किए गए उत्पाद जैसे तोलिए, पर्दे, सोफा सेट कवर, साबुन, शैम्पू अपने होटल में प्रयोग करने पर विचार कर रहा है। साथ ही केवीआईसी देशभर में स्थित हवाई अड्डों पर अपने आउटलेट खोलने की योजना बना रहा है।

वर्तमान में आईटीडीसी (इंडियन टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन) के अलग अलग शहरों में 16 होटल हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पर्यटन मंत्रालय के आधीन है। दिल्ली में इसके तीन होटल है और बाकी जम्मू, रांची, भुवनेश्वर, पुरी पटना, भोपाल, भरतपुर, जयपुर गुवाहाटी, पुडुचेरी, मैसूर व इटानगर में हैं।

पिछले महीने श्री अमित शाह ने खादी के प्रचार-प्रसार के लिए संस्कृति व पर्यटन मंत्री श्री महेश शर्मा को खत लिखा था। एयर इंडिया के क्रू मैंबर पहनेंगे खादी, पीएम की यात्रा से हुई थी शुरुआत।

डी.एल.टी.एफ.सी. द्वारा आयोग की पीएमईजीपी योजना के तहत 26 आवेदनों की सिफारिश

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण अंडमान से प्राप्त ऋण आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु दक्षिण अंडमान के उपायुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री विजय कुमार बिधुरी के अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की 53 वीं बैठक 6 मई, 2016 को आयोजित की गई थी।

इस बैठक में उद्योग निदेशक श्री एम.एन. मुरली, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महा प्रबन्धक श्री रबी कुमार साहा, भारतीय स्टेट बैंक के एल.डी.एम, एल.बी.ओ, श्री पी.के. उमेर फारुक, डी.बी.आर.ए.आई.टी के मुख्य श्री अरुण श्रीवास्तव, एन.वाय.के.एस के जिला युवा सयोजक श्री कुन्दन लाल, पोर्ट ब्लेयर, एम.एस.एम.इ.-डी.आई. के सहायक निदेशक श्री एम.के. अंजनाइयाह, सिंडीकेट बैंक के प्रबन्धक श्री श्रीनिवास वज्जा उपस्थित थे।

स्वच्छ भारत - स्वच्छ आयोग

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण कुमार झा के
नेतृत्व में आयोग मुख्यालय में स्वच्छ अभियान चलाया गया।

गांधी और खादी:एक प्रासंगिक अनुचिंतन

-डॉ.चन्द्रकुमार जैन

खादी के धागे धागे में
अपनेपन का अभिमान भरा,
माता का इसमें मान भरा
अन्यायी का अपमान भरा।

खादी के रेशे-रेशे में
अपने भाई का प्यार भरा,
माँ-बहनों का सत्कार भरा
बच्चों का मधुर दुलार भरा।

खादी की रजत चंद्रिका जब
आकर तन पर मुसकाती है,
तब नवजीवन की नई ज्योति
अन्तस्तल में जग जाती है।

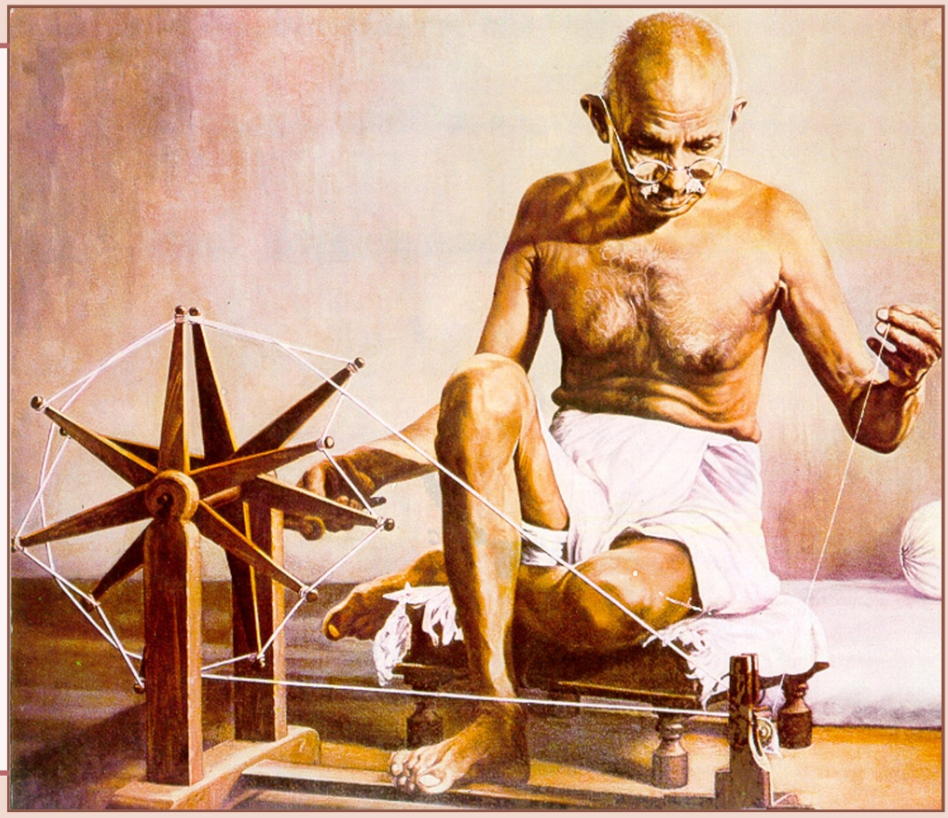

कवि श्रेष्ठ सोहल्लाल द्विवेदी की उक्त पंक्तियाँ खादी के विषय में बड़ी मर्म की बात कह देती हैं। फिलहाल, यह वास्तव में उत्साहवर्धक है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि खादी के जरिये भारतवासियो को स्वाबलंबी बनाने के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को उनकी सरकार आगे बढ़ा रही है और विभिन्न सरकारी संस्थान आगे बढ़कर खादी के उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। दरअसल, मुझे लगता है कि गांधी जी के स्मरण दिवस पर नए सिरे से लोगों तक पहुंचे ये उद्गार खादी को लेकर बापू की सोच की व्यापकता को स्वर देने की नई पहल के समान है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रसंग ने मुझे 'खादी और गांधी' के फलसफे पर पलटकर देखने और उनके फलसफे को साझा करने की प्रेरणा दी है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नव गठित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग नये अवसरों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। इन पहलों के तहत सौर चरखा और सौर लूम से उत्पादन के सफल प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा से चलने वाले चरखा और लूम से बुनकर पहले से कम मेहनत में अधिक उत्पादन और दोगुनी आमदनी पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली खादी आज एक फैशन परिधान बन गई है और सरकार भारत के गांव गांव में खादी और ग्रामोद्योग का नेटवर्क तैयार करना चाहती है। इससे लोगों को रोजागार से जोड़कर गांव के प्रत्येक परिवार को सबल बनाया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री जी ने कहा, '' मैंने कल पूज्य बापू की पुण्य

तिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों तक पहुंच सकता हूं, मैंने पत्र लिख कर पहुंचने का प्रयास किया। '' उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जतायी कि खादी के उत्पादों का उपयोग करने के लिए रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौसेना, डाक विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थान आगे आ रहे हैं । इसके चलते लगभग 18 लाख मानव दिवसों का अतिरिक्त रोजगार खादी के क्षेत्र में उपलब्ध होगा और इससे प्रत्येक कारीगर की आमदनी में बढोत्तरी होगी ।

बहरहाल, जैसा कि मैंने पहले ही लिखा कि खादी पर गांधी जी के दृष्टिकोण में निहित और सूत के एक-एक धागे के साथ जुड़ी स्वाधीनता, संवेदना, आत्म सम्मान की भावना को समझना आज भी समझदारी की बात है। वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने चरखे के चक्र में कल की गति के साथ ताल मेल करने और उससे होड़ लेने की भी अनोखी शक्ति को गहराई से देख लिया था। खादी के जन्म की कहानी भी काम रोचक नहीं है।

अपनी आत्म कथा में बापू लिखते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि सन् 1908 तक मैने चरखा या करधा कहीं देखा हो । फिर भी मैनें "हिन्द स्वराज" मे यह माना था कि चरखे के जरिये हिन्दुस्तान की कंगालियत मिट सकती है । और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन् 1915 मे मै दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान वापस आया, तब भी मैने चरखे के दर्शन नही किये थे । आश्रम के खुलते ही उसमें करधा शुरू किया था । करधा शुरू करने मे भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पडा । हम सब अनजान थे, अतएव करधे के मिल जाने भर से करधा चल नही सकता था । आश्रम मे हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे , हममे कोई कारीगर नही था । इसलिए करधा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी । काठियावाड़ और पालनपूर से करधा मिला और एक सिखाने वाला आया । उसने अपना पूरा हुनर नही बताया । परन्तु मगनलाल गाँधी शुरू किये हुए काम को जल्दी छोडनेवाले न थे । उनके हाथ मे कारीगरी तो थी ही । इसलिए उन्होने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम मे एक के बाद एक नये-नये बुनने वाले तैयार हुए ।

आगे गांधी जी लिखते हैं कि हमे तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे । इसलिए आश्रमवासियो ने मिल के कपड़े पहनना बन्द किया और यह निश्यच किया कि वे हाथ-करधे पर देशी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेगे । ऐसा करने से हमे बहुत कुछ सीखने को मिला । हिन्दुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने मे होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमे वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन-दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सबकी जानकारी हमे मिली । हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरन्त बुन सके, ऐसी स्थिति तो थी ही नही। कारण से बाहर के बुनकरों से हमे अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवा लेना पडता था। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नही था । बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती

सूत का ही बुनते थे , क्योकि हमारी मिलें सूत कातती नहीं थी । आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही कातती है , बहुत महीन तो कात ही नही सकती । बडे प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे , जिन्होने देशी सूत का कपडा बुन देने की मेहरबानी की ।

इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जायेगा । इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रो मे उसका प्रचार किया । यों हम कातने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने । मिलो के सम्पर्क मे आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमे मिली । हमने देखा कि मीलों का ध्येय खुद कातकर खुद ही बुनना था । वे हाथ-करधे की सहायता स्वेच्छा से नही , बल्कि अनिच्छा से करती था । यह सब देखकर हम हाथ से कातने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से कातेगे नही, तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी । मीलों के एजेंट बनकर देश सेवा करते है , ऐसा हमे प्रतीत नहीं हुआ ।

लेकिन गांधी जी के अनुसार न तो कही चरखा मिलता था और न कही चरखे का चलाने वाला मिलता था । कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काता जा सकता है इसका तो हमे ख्याल ही नहीं था । एक बार कालीदास वकील एक बहन को खोजकर लाये । उन्होने कहा कि यह बहन सूत कातकर दिखायेगी । उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा , जो इस विषय मे कुछ बता सकता था, मैं पूछताछ किया करता था । पर कातने का इजारा तो स्त्री का ही था । अतएव ओने-कोने मे पड़ी हुई कातना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी।

बापू स्पष्ट करते हैं कि सन् 1917 मे मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोच शिक्षा परिषद मे घसीट ले गये थे । वहाँ महा साहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली । वे पढी-लिखी अधिक नही थी , पर उनमे हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनो मे होती है उससे अधिक थी । उन्होंने अपने जीवन मे अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी, वे बेधड़क अंत्यजों मे मिलती थीं और उनकी सेवा करती थी । उनके पास पैसा था , पर उनकी अपनी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं । उनका शरीर कसा हुआ था । और चाहे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी । वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी । इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद मे प्राप्त हुआ । अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज मे भटकी थी, उसी प्रकार चरखे की खोज मे भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हलका कर दिया ।

गांधी जी ने 1920 के दशक में गावों को आत्म निर्भर बनाने के लिये खादी के प्रचार-प्रसार पर बहुत जोर दिया था । जरा सोचें कि हम विज़न 2020 में शामिल कर उसी खादी को एक नई पहचान देकर बापू की उस देशभक्ति से परिपूर्ण मुहिम को शताब्दी वर्ष के रूप में सन 2020 में धूमधाम से नहीं मना सकते ?

लेखक प्रेरक वक्ता, कुशल प्रशिक्षक,सजग सचेतकऔर शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव में प्रोफ़ेसर हैं।

मधुमक्खी पालन उद्योग

भारत में शहद और मधुमक्खी पालन का इतिहास बहुत ही पुराना है। शहद, पहाड़ी गुफाओं और जंगलों में रहने वाले प्राचीन भारतीय द्वारा चखा गया पहला मीठा भोजन था। उन्होंने इस दैवीय उपहार के लिए मधुमक्खियों के छत्ते की खोज की। भारत के प्रागैतिहासिक मानव द्वारा कंदराओं में चित्रकला के रूप में मधुमक्खी पालन का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। सभ्यता के विकास के साथ शहद ने प्राचीन भारतियों के जीवन में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। वे शहद को जादूई पदार्थ मानते थे जो महिलाओं, मवेशी तथा उनकी भूमि और फसल की उर्वरता को नियंत्रित करता था। वर्तमान में, उप हिमालय पर्वतीय श्रेणी तथा पश्चिमी घाट जहाँ इसकी प्रक्रिया सामान्य रूप में होती है, सहित सघन वनीय श्रेत्रो में उद्योग का प्रमाण है।

भारत में मधुमक्खी पालन मुख्यत: वन आधारित होता है। अनेकों प्राकृतिक वनस्पति प्रजातियाँ शहद के लिए नेक्टर और पॉलेन प्रदान करती है। अत: शहद उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रकृति से मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। मधुमक्खी के छत्ते के लिए न तो अतिरिक्त भूमि लगती है और न ही किसी उपकरण हेतु कृषि अथवा पशुपालन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलनियों की निगरानी हेतु केवल कुछ घंटे बिताना पड़ता है। इसलिए, मधुमक्खी उनका पालन आंशिक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण तथा जनजाति किसानों के लिए धारणीय आय सृजन का साधन बनाता है। इससे उन्हें शहद, प्रोटीनयुक्त पॉलेन एवं ब्रूड़ जैसे मूल्यवान पोषण मिलते है।

परम्परागत ग्रामोद्योग के पुनरूद्धार हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना से ही मधुमक्खी पालन के विकास की देखभाल हुई है। वर्ष 1980 के दौरान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विविध योजनाओं के अंतर्गत लगभग एक मिलियन मधुमक्खी छता ने कार्य किया था। देश में एपियरी शहद का उत्पादन 10,000 टन होता है जिसका मूल्य लगभग रू.300 मिलियन है।

देशज मधुमक्खी, एपिस सेरेना, यूरोपिय मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पालन ने जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में प्रसिद्धि प्राप्त की। वृहत शहद मधुमक्खी तथा प्राच्य छता मधुमक्खी की अन्य शहद मधुमक्खियों ने शहद संग्रह हेतु नष्ट किया जाता है। भारत के अनेक भागों में जनजाति जनसंख्या तथा वन निवासी जंगली शहद मधुमक्खी से शहद संग्रह करते है क्योंकि यह उनका पारंपरिक व्यवसाय है। इन घोसलों से शहद एवं मोम संग्रह की विधि धीरे-धीरे बदल चुकी है।

इस शहद का मुख्य उत्पादन क्षेत्र उप हिमाचल तथा समीप के पहाड़ी क्षेत्र, उष्ण कटिबन्धीय वन सहित वन एवं फार्म है तथा इसकी खेती राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उडीसा और आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में की जाती हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग संबंधित सुर्खियां....

THE HINDU

DELHI, MONDAY, MAY 2 2016

IGIA spins larger-than-life yarn

The four-tonne teakwood charkha is being installed by KVIC at Delhi airport

SIDHARTHA ROY

NEW DELHI: India's biggest and busiest airport will now have something new to boast about — the world's biggest charkha.

The larger-than-life charkha is 27-foot wide and 15-foot tall. The four-tonne teakwood charkha has been installed by the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) at the Indira Gandhi International Airport here. Airport's private operator Delhi International Airport Ltd. (DIAL) has statutory right on Terminal 3 for allotment of land and space in and around the terminal.

"The charka is a symbol of India's Independence and non-violence. We felt the world's largest charkha should come up at the Delhi airport, which is visited by lakhs of people every day-...people should know what a charkha is," KVIC chairman V.K. Saxena told *The Hindu*.

"Gandhiji made the charkha a weapon for India's Independent and it is very important for India. It is also a symbol of India's rural prosperity. Lakhs of people are running the charkha in the remotest corners of the country," Mr. Saxena added.

The charkha was built in Ahmedabad by 42 carpenters, who took over 50 days to complete the work. It was brought to the airport in trucks.

"It is made of pure teakwood, which is very costly," he said. The charkha also commemorates the centenary year of Mahatma Gandhi's arrival from South Africa.

Mr. Saxena said the display of the world's biggest charkha at the Capital's "busiest airport" will also inculcate the feeling of *swadeshi* among both domestic and international travellers. In a meeting held on January 13 between Mr. Saxena and DIAL CEO I. Prabhakar Rao, DIAL agreed to allot space for putting up the charkha at the departure forecourt between gates number 4 and 5.

DESI DISPLAY: The charkha was built in Ahmedabad by 42 carpenters over 50 days and brought to Delhi in trucks. — PHOTO: SPECIAL ARRANGEMENT

ams Modi
o blank out
-Gandhis

TIGER ROARS AT BJP

May 26 | Saamna criticizes Modi govt as it completes two years in office, says it made tall promises but failed miserably to deliver

May 29 | Says results of five Assembly polls have gone against BJP

May 12 | Sena hits out at BJP over Uttarakhand, saying if it continued its ways, India would move towards another Emergency-like situation

April 7 | Saamna says BJP's cheap politics over 'Bharat Mata Ki Jai' will not help resolve the water crisis in Maharashtra

Pouring ridicule on Modi's latest assurance that strengthening states would be his government's priority, Saamna asked if states ruled by non-BJP governments would also be strengthened by the NDA.

▶Continued on P 8

Khadi, village product sales soar 14% to ₹36,425 crore

Sidhartha@timesgroup.com

New Delhi: India Inc may be complaining of weak rural sales due to poor rains for two years in a row, but khadi and village industries, which manufacture products ranging from honey to soaps and food to handicraft, are clocking a double digit growth.

Data available with **TOI** showed that khadi and village industries sales shot up 14% to Rs 36,425 crore during 2015-16, while top FMCG players reported a much lower sales growth. The exception perhaps is Ramdev's Patanjali, which claimed to have more than doubling its turnover to Rs 5,000 crore last year.

Unlike FMCG firms that largely rely on their own plants for production, khadi and village industry products are manufactured by around seven lakh privately owned household units.

▶Khadi fabric sale, P 16

Kalraj Mishra Appreciates JK Govt for PMEGP

Srinagar | Agencies

Appreciating the work of State Government in Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) during 2015-16, the Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Kalraj Mishra on Sunday said that 23,140 people of Jammu and Kashmir were employed in 3,772 PMEGP units across the state.

The minister added that a record sum of approximately Rs 38 crores was utilised in past two years for assisting a record number of more than 2200 PMEGP units in Jammu and Kashmir. "During the last two years more than 6,80,000 persons were employed by setting up of 92,508 PMEGP units in whole of India. Out of which 23,140 persons were employed in 3,772 units in the state of Jammu and Kashmir," Mishra said while addressing a press conference here on Sunday.

Earlier, the Union Minister inaugurated and addressed to the participants of PMEGP workshop at institute of Hotel Management Rajbagh, here. Jammu and Kashmir Minister for Industries and Commerce, Chander Parkash Ganga was also present on the occasion.

Khadi fabric sales up by 29%, cross ₹1,500cr mark for the first time

▶ From P 1

These desi units are funded through schemes such as PM's Employment Generation Programme. A small part of the produce is sold through Khadi Boards and outlets owned by Khadi and Village Industries Commission (KVIC). The majority of products, which could be henna, papad or agarbattis, is directly sold through private shops.

Unlike Patanjali, which has launched a high-decibel campaign, village industry sales have been driven by an aggressive distribution push, including to institutional buyers such as Air India and Indian Railways, said KVIC chairman VK Saxena.

Air India for instance has placed a *Rs 8* crore order to source khadi products for kits for first and business class travellers.

Khadi fabric and garment sales witnessed a 29% growth and crossed Rs 1,500 crore mark for the first time. While the government is pushing khadi, there is also a change in the sales mix with ready-made garments now accounting for around 45% compared to nearly 30% two years ago.

KVIC is now tying up with Paytm to offer "high-end products" online. It has also entered into arrangements with companies such as Raymond and Fabindia. Sources said that KVIC will for the first time also enter into franchise agreements for around 20 new stores in Kolkata and Mumbai, with Delhi expected to join later.

SLOWDOWN PROOF?

Change in sales between 2015-16 and 2014-15

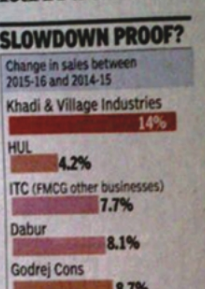

Unlike Patanjali, which has launched a high-decibel campaign, village industry sales have been driven by an aggressive distribution push, including to institutional buyers such as Air India and Indian Railways

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग संबंधित सुर्खियां....

एयर इंडिया क्रू की होगी नई यूनिफॉर्म!

■ एजेंसी, नई दिल्ली : एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स का मेकओवर होने वाला है और जल्द ही ये नई ड्रेस में नजर आएंगे। कंपनी की एक इंटरनल कमेटी ने कई तरह की यूनिफॉर्म की सलाह दी है। कमेटी में ज्यादातर इन-फ्लाइट स्टाफ हैं। केबिन क्रू के जनरल मैनेजर ने 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।

एयरलाइंस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कमेटी ने पैटर्न, मैटीरियल और रंगों से जुड़े कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इस मामले में फैसला लेने से पहले कमेटी की रिपोर्ट का मूल्यांकन कर रहा है। एयर इंडिया में केबिन क्रू की संख्या करीब 4000 है।

अधिकारी ने कहा कि मैनेजमेंट प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' को ध्यान में रखते हुए संभावनाओं पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'कमेटी ने जो विकल्प सुझाए हैं उनमें से एक स्वदेशी फैब्रिक खादी का इस्तेमाल है।' राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति की ऑफिशियल एयरक्राफ्ट एयर इंडिया वन के हालिया बेल्जियम और अमेरिका दौरे पर केबिन क्रू ने खादी के यूनिफॉर्म पहने थे। अधिकारी ने कहा, 'ऐसा पहली बार हुआ है, जब एयरलाइन में ऐसी कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें हर रीजनल बेस और बेड़े का केबिन क्रू शामिल है। इसका मकसद उन्हें ऐसा यूनिफॉर्म चुनने की आजादी देना है, जिसमें वे आरामदायक महसूस करें।' अधिकारी ने कहा, 'कमेटी की सुझावों के आधार पर कपड़ों के सैंपल तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद आखिरी फैसले के लिए इन्हें अथॉरिटी को सौंपा जाएगा।'

Cluster development would enhance the competitiveness of business : Kalraj Mishra

Mumbai| Our correspondent

Addressing the Outlook business programme Union MSME Kalraj Mishra said, the cluster development would enhance the competitiveness of business in changed economic scenario and encourage entrepreneurship, employment and livelihood opportunities also stressed on skill dev, supportive and cohesive environment for the young India. He also informed on initiative taken for udyog adhar memorandum which requires minimum information for registration. Good plan and determination can executive your dream of becoming an entrepreneur into reality, he added.

In his talk he also mentioned about stand up India and start up India, MSME takes care of their needs, he said. MSME with its hard work will rewrite the story of industrialisation of modern 21st century India.

Mehbooba asks

Durbar move

Mehbooba bats

Militants dec

Facts expos

We requir

लॉस एंजिल्स में दमकी राजस्थानी खादी

जयपुर खादी को अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी काफी सराहना मिल रही है और फैशनेस खादी से जुड़े डिजाइनर कलेक्शन को स्टाइल स्टेटमेंट भी बना रहे है। इसकी बानगी लॉस एंजिल्स में आयोजित स्टाइल स्टेटमेंट फैशन वीक में नजर आई। शहर की डिजाइनर राजनील बबूता ने इस फैशन वीक में खादी से जुड़े कलेक्शन को पेश किया। कलेक्शन में उन्होंने साड़ी, लॉन्ग अनारकली, जैकेट्स, स्कर्ट और ट्राउजर्स को डिफरेंट अंदाज में रैम्प पर उतारा। फैशन वीक में हिस्सा लेकर लौटी राजनील ने कहा कि मैंने शो के लिए भागलपुरी, रॉ और प्योर सिल्क में हैंड वर्क और प्रिंट के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ऑफ व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, ग्रे कलर्स में गारमेंट्स तैयार किए थे।

केंद्र को महबूबा की चेतावनी
अगर कश्मीरियों को कोई उंगली दिखाएगा तो वह मुक्का खाएगा

■ भारत-पाक बंटवारे के बाद मुसीबत में फंस गया जम्मू-कश्मीर
■ पाक के साथ-साथ भारत में भी कुछ लोग अमन नहीं चाहते

KVIC को मिलेगा 1 हजार चरखा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भी खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है.केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने केवीआईसी को 1 हजार चरखा और 200 लूम देने का ऐलान किया है.आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना और पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में उपरांत ऊर्जा मंत्री ने यह घोषणा की है.गोयल ने कहा कि केवीआईसी को दिए 200 लूम के माध्यम से वाराणसी विभाग में लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे.

उत्पादन बढ़ाने की तैयारी

केवीआईसी ने निकट भविष्य में खादी का उत्पादन कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.जिसके लिए आगामी कुछ माह में केवीआईसी ने 10 हजार सोलर चरखा वितरित करने की योजना बनाई है.साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इस उद्योग से जोड़ने के लिए आयोग द्वारा देश के कई हिस्सों में प्रशिक्षण शिविर भी चलाया जा रहा है.ताकि सूखा समेत अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों को रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध करवाए जा सके.

खादी का बढ़ता क्रेज

■ खादी का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है.रेलवे,एयर इंडिया,डाक और उत्तराखंड के कई सरकारी विभागों द्वारा खादी अपनाने के बाद ऊर्जा विभाग में कार्यरत कर्मचारी भी जल्द खादी में नजर आएंगे.

■ खादी को प्रोत्साहित करने के लिए पीयूष गोयल ने ऊर्जा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों में कार्यरत कर्मचारियों को खादी के कपड़े पहनने की अपील की.सरकारी विभाग के साथ कई निजी संस्थान भी खादी को बढ़ावा देने में जुट गई हैं.

■ इसके तहत विनय कुमार सक्सेना के पहल के बाद जे.के सीमेंट ग्रुप ने अपने सभी प्लांट, ऑफिस और स्कूलों में पढने वाले छात्रों को यूनिफॉर्म के रूप में खादी का इस्तमाल करने का आदेश दे दिया है.

अदालती झंझट से मिलेगी मुक्ति

सुशील मिश्र
मुंबई, 5 मई

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने काम में पारदर्शिता लाने एवं अदालतों में चल रहे मुकदमों को समय पर निपटाने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग चाहता है कि अधिकांश मामले अदालत के बाहर ही आपसी समझ से निपटा दिए जाएं। वर्तमान समय में चल रहे सभी विवादित वित्तीय मुकदमों को अगले साल तक खत्म करने की योजना तैयार की गई है।

लघु एवं कुटीर उद्योग को संरक्षण देने वाला देश का सबसे बड़ा संस्थान खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने सदस्यों को मुकदमेबाजी से मुक्त करने की योजना तैयार कर चुका है।

इसके तहत आयोग ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है साथ ही न्यायिक मामलों से संबंधित एक पुस्तिका भी तैयार की गई है। इसके तहत पुराने विवादों को समझने और नए विवादों को पनपने से रोका जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को चल रहे न्यायिक मुकदमों को न्यायालय के बाहर ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे समय, धन और मुकदमेबाजी से होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि अगले साल तक मुकदमों की संख्या शून्य कर दी जाए और यह तभी संभव है जब अदालत के बाहर इन्हें निपटाने का काम किया जाए। कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए विधि विभाग ने ऑनलाइन निगरानी की जो शुरुआत की है वह मामलों के निपटाने में बहुत सहायक साबित होगी। खादी और ग्रामोद्योग के अधिकारियों के मुताबिक इस समय करीब 842 मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं जिनमें ज्यादातर वित्तीय लेन देन के हैं। जो मामले अदालत में हैं उनका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि ज्यादातर मामले आपसी समझ से हल किए जा सकते थे जैसे देरी से भुगतान, समय पर माल न पहुंच पाना, काम से संतुष्ट न होना या लेटलतीफी के कारण लोग अदालत गए हैं। जो मामले अदालत में है वह काफी समय से चल रहे हैं इससे लोग परेशान होते हैं। दरअसल अदालतों में काम अधिक होने के कारण छोटे छोटे मामले भी वर्षों चलते रहते हैं। ऐसे में दोनों पक्ष परेशान होते हैं। इस तरह के मामलों के निपटाने के लिए आयोग एक टीम की नियुक्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी कामों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग संबंधित सुर्खियां

एमएसएमई को 21 वीं सदी के भारत के औद्योगीकरण की कहानी को फिर से लिखना होगा: कलराज मिश्र

मुंबई। मुंबई में आउटलुक बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 17 मई 2016 को माननीय केंद्रीय मंत्री एमएसएमई ने कहा, क्लस्टर विकास बदले आर्थिक परिदृश्य में व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और साथ साथ भारत के युवाओं के लिए सहायक और एकजुट पर्यावरण को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने उद्योग अधर ज्ञापन में पंजीकरण के लिए न्यूनतम जानकारी की आवश्यकता के लिए की गई पहलके बारे में भी जानकारी

दी। उन्होंने कहा की हम योजनाओं में से अधिकांश को मांग और जरूरत के आधार पर संचालित कर रहे हैं जो की इसको उद्यमी के अनुकूल बनाता है। विभिन्न समूहों में कुल 1018 आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना 29 से अधिक राज्यों में की जानी है जिनमे से 677 केंद्रों का काम पूरा हो चुका है और 178 में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन किया जाना है जिसमें से 126 केंद्रों का उन्नयन किया जा चूका है। उन्होंने कहा की एमएसएमई के विकास का राष्ट्रीय उद्देश्य राष्ट्र का विकास है और इसका देश के आर्थिक विकास पर एक बहु असर पड़ेगा। उन्होंने टूल रूम की स्थापना करके पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्यमों में सार्वजनिक खरीद पर बल दिया और कहा कि वह 20% से 20% अनिवार्य एमएसई द्वारा खरीदा जाना चाहिए।

Juma mubarak has become 'juma pathrav': Mehbooba

'CM's chair crown of thorns for me, chosen by Mufti to open Delhi's coffers for J&K'

JUNAID NABI BAZAZ ■ SRINAGAR

Chief Minister Mehbooba Mufti on Sunday asked youth not to indulge in stone pelting every Friday, and defended her father's decision to alliance with Sangh Parivar's key player, the BJP.

"Our prophet Mohammad (SAW) taught us to wear clean clothes, use ittar (natural perfumes) on Friday but our elders have to think ten times whether to go to mosque on a Friday because Juma Mubarak have become 'juma pathrav'. This is wrong. Kashmiris have to reform themselves," Mehbooba told a public gathering... ga! Magar tum ek kadam chalo ge, ye dus kadam chalega. (If the Indian government shows a finger to Kashmiri youth, they will show you the fist. But if you walk a step towards them, they will take ten)"

She said that the decision to make the state part of India 'was a wise one' and the ongoing strife is only the consequence of Indian subcontinent's partition.

"The people of state were not party to partition yet people are bearing its burnt. People were not asked weather to go Pakistan or not because of which they have been facing the problems in the state," said Me...

JK not benefiting much from GoI schemes: minister

JUNAID NABI BAZAZ ■ SRINAGAR

State entrepreneurs have shown little interest in Indian government's latest initiative of ease of doing business, government of India minister for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Kalraj Mishra said on Sunday.

In September last year, the Indian government had started online registration for starting new industrial units across India, replacing the old method of door-to-door registration.

Compared to 6.60 lakh entrepreneurs across India who have registered online, only 84 units have been registered in JK through this mode in the past seven months, Mishra said.

He said that only one industry--he did not specify which--has availed of the benefits of MSME ministry's Credit Link Capital Scheme. The scheme, as per the website of MSME, offers collateral-free credit from financial institutions.

"J&K is not deriving full benefits of various schemes. I ask the state government to come up with more ... more assistance," Mishra said.

... claimed that in ... Employment Generation Programme (PMEGP), the India government's spending of Rs 38 crore, has employed 23,140 people in the state in the last financial year (2015-16).

"Land has already been identified for such a technological center. Four clusters have already been started while three will complete soon. The PM's employment generation program will ensure that youth here are empowered," Mishra said.

Asked why 21 schemes of the ministry have not been extended to the state, Mishra said his future endeavors would make their execution possible.

"Several technological centers will be set up here for conducting research and development that would benefit start-up and entrepreneurs. The state will soon witness completion of seven clusters. This will make the implementation possible," he added.

On the occasion, State Industries and Commerce Minister Chander Prakash Ganga said the current functioning of industry in the state has to change.

"The ongoing system which has been inherited from the last 60 years is in shambles. The problems we face are because of this system. Our government has come for the change and its results will be displayed soon," Ganga said.

Don't know why Guru was hanged, says Mehbooba

Hails 'humility of Indian Muslims', says 'Kashmir youth need to be brought into mainstream'

SAQIB MALIK

Srinagar, May 8: Three years after the secret execution of Muhammad Afzal Guru in New Delhi's Tihar Jail, the J&K Chief Minister Mehbooba Mufti on Sunday said she is still to understand why and what for he was hanged.

Addressing a gathering at the inauguration of Khadi Exhibition at Kashmir Haat here, Mehbooba recalled the hanging of Guru on February 9, 2013, saying his execution evoked a "strong discussion across the board, something unlikely in a country like Pakistan."

"Here one Kashmiri was hanged. We don't even know why he was hanged or what he was hanged for. He was picked up from 28 serial number and hanged. But I am proud of people of India, our Hindu brethren, Muslims, media, academicians, [that] all of them protested his hanging. This is the beauty of this nation. Where does this happen? We have a democratic setup, anyone can put his point," she said.

"We have a great nation, a democratic nation. If we look at our neighbouring nation (Pakistan) so many are hanged there in a month. From children to Zulfiqar Ali Bhutto, so many were hanged. But no one can open his mouth there," she said.

Mehbooba hailed Indian Muslims for their humility and peace-loving nature.

"If you go to America or Europe and show your Indian passport, they will not create any hassles. This is because Muslims of our country are very peaceful. So I believe our future has been embedded with this country. Our

» See Don't know...on Pg-10

> This alliance was not created so that late Mufti Sahab or me would become the Chief Minister. It's not a big thing. This is a crown of thorns for people like us. But we accepted this crown of thorns with an expectation that you (Centre) will open your treasuries for the people of Jammu and Kashmir.
>
> This is Kashmir. If you take one step, they (people) will take 10 towards you. But if you show them a finger, they will show you the fist. That is why when Vajpayee took one step, our people took ten towards him.
>
> Mehbooba Mufti, CM

2022 तक 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे : कलराज

अमर उजाला ब्यूरो

श्रीनगर। केंद्रीय सरकार वर्ष 2022 तक 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। 18 टूल रूम और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटरों में एक लाख युवाओं को वर्तमान में लघु और दीर्घ अवधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समय में यह पैमाना व्यापक स्तर तक ले जाया जाएगा। माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइसेज केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने श्रीनगर में ये बातें कहीं। सेल्स भंडार के उद्घाटन समारोह में आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर के लघु उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष योजना बनाई है। लघु और खादी औद्योगिक इकाइयों को केंद्र विशेष सहायता प्रदान करेगा। छोटे उद्योग अपने पांव पर खड़े हो सकें, इसके लिए बुनियादी जरूरतों के अनुसार सहायता देने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री इंप्लायमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी कार्य श्रृंखला को कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सेल्स भंडार का उद्घाटन किया और तीन ई-चरखा इकाइयों का जायजा लिया। कलराज मिश्र ने कहा राज्य सरकार का उद्योग विभाग ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इससे पूर्व राज्य के उद्योग मंत्री चंद्रप्रकाश गंगा ने कहा राज्य को अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। सेल्स भंडार प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए वक्ताओं ने बताया प्रदर्शनी एक महीने तक चलेगी। देश भर से 200 स्टाल लगाए गए हैं। इनमें 100 स्टाल राज्य के स्थानीय हैं।

श्रीनगर में शनिवार को सेल्स भंडार का उद्घाटन करते कलराज मिश्र।

CM meets MSME minister
Mehbooba seeks New Delhi's help to revitalize local industry

Highlights potential of bat, leather, rice, papier machie clusters; asks for enhancement of PMEGP target from 1500 to 4000

Mishra urges banking sector to create entrepreneurship culture in JK

National khadi exhibition inaugurated at Kashmir Haat

इस गर्मी बरकरार है खादी की चमक

- पिछले वर्ष की तुलना में खादी के परिधानों की बिक्री में 30 फीसद की बढ़ोतरी
- खादी के लहंगे और दुपट्टे लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: इस गर्मी में खादी की चमक बरकरार है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खादी परिधानों की बिक्री में करीब 30 फीसद तक तेजी देखने को मिल रही है। खादी परिधानों की बिक्री से जुड़े लोग ग्राहकों के इस रुख से उत्साहित हैं। उनके मुताबिक यह चलन आगे भी बना रह सकता है, क्योंकि खादी को आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में भी खादी के परिधान खरीदने को लेकर प्रेरित किया था। खास बात कि गर्मी में खादी के कपड़े शरीर को सुकून देते हैं। ऐसे में कुर्तों की मांग ज्यादा है। उसमें भी नरेंद्र मोदी कट कुर्ता।

कनॉट प्लेस के रिगल बिल्डिंग के नजदीक स्थित खादी ग्रामो उद्योग के आउटलेट्स में कई नए डिजाइन के परिधान ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। खास बात कि इसमें विदेशी खरीदार भी शामिल हैं।

खादी के परिधानों के प्रति लोगों को लुभाने के लिए 13 अप्रैल से समर कलेक्शन चल रहा है, जिसमें खरीदारी पर 30 फीसद की छूट भी मिल रही है। आउटलेट्स में सभी की पसंद का ख्याल रखा गया है। कर्मचारी रोहित कुमार ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। इस बार लंबे और मोदी स्टाइल कुर्ते खूब चलन में है।

आउटलेट्स में खादी के उत्पादों के साथ-साथ सिल्क की साड़ियां, लहंगे, सूती सूट, दुपट्टे, कुर्ते की भी खूब मांग है। इनमें से महिलाओं व पुरुषों के कुर्ते 500 से 2000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। साथ ही सिल्क की साड़ियां 1000 से 6000 रुपये के बीच उपलब्ध हैं। खादी से बने लहंगे तथा दुपट्टे के कई किस्में भी उपलब्ध हैं। खादी ग्रामोद्योग के निदेशक डी एस भाटी ने बताया कि इस बार खादी की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका कारण लोगों का खादी की ओर आकर्षित होना है।

कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में गर्मियों के लिए खास स्टॉल लोगों को काफी लुभा रहे हैं।

पुस्तिका का लोकार्पण एवं आनलाइन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ

मुंबई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना द्वारा आयोग के न्यायिक मामलों से संबंधित एक पुस्तिका का लोकार्पण एवं आयोग के चल रहे मुकदमों हेतु आनलाइन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय मुंबई किया गया। इस अवसर पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार झा, वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी उपस्थितों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने दोहराया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चल रहे न्यायिक मुकदमों को न्यायालय के बाहर ...रने की कोशिश करनी चाहिए जिससे समय, धन और ऐसी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बचा जा सके। आयोग के विधि विभाग की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आनलाइन निगरानी प्रणाली कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने में बहुत सहायक होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष से हमारा प्रयास अदालती मामलों को शून्य स्तर तक कम करने का होगा।

Khadi India

स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाईट : www.kvic.org.in

भारत में हम रोजगार सृजन करते हैं तथा समृद्धि बुनते हैं